जानलेवा बुखारों का कहर

साल के पहले पांच सप्ताहों में ही देश में स्वाइन फ्लू के 6,701 मामले सामने आये हैं. इस बीमारी से अब तक 226 मौतें ही चुकी हैं. इसी अवधि में पिछले साल इससे सिर्फ 798 लोग बीमार हुए थे और मृतकों की संख्या 68 रही थी, लेकिन पूरे साल में करीब 15 हजार लोग इस फ्लू की चपेट में आये थे और मरनेवालों की संख्या 1,103 रही थी. हालांकि, पीड़ित देश के कई राज्यों में हैं, पर फिलहाल राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सर्वाधिक प्रभावित हैं. चूंकि फ्लू का असर एक साल के अंतराल पर कम या ज्यादा होता रहता है, तो अनुमान यह है कि इस साल मरीजों की तादाद बहुत बढ़ सकती है. इसमें एक कारण जाड़े के मौसम का लंबा होना भी है. मौसम गर्म होने के साथ शायद स्वाइन फ्लू के विषाणुओं का कहर कम होने की उम्मीद की जा रही है. दिल्ली में डेंगू का एक मामला भी सामने आया है. हालांकि, राजधानी में मलेरिया और चिकनगुनिया से अभी कोई पीड़ित नहीं है, पर आगामी दिनों में दिल्ली और अन्य राज्यों में इनके असर से इनकार नहीं किया जा सकता है. इस संबंध में कुछ बातों को रेखांकित करना जरूरी है. मौतों में कमी यह इंगित करती है कि बीते अनुभवों के आधार पर स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में उपचार बेहतर हुआ है. इसका दूसरा पहलू यह है कि मृतकों में ज्यादातर वैसे लोग हैं, जिन्हें पहले से सांस-संबंधी बीमारियां, रक्तचाप और मधुमेह की शिकायत थी. यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसी बीमारियों में प्रदूषण एक बड़ा कारण है तथा हमारे शहरों में वायु एवं जल प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है. इस कारण दवाओं का असर कम होता है और अन्य बीमारियां फ्लू को अधिक घातक बना देती हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के साथ निरंतर संवाद कर मौसमी बुखारों की स्थिति पर नजर रख रही है. स्वाइन फ्लू समेत अन्य मौसमी बुखार दुनिया में हर साल 30 से 50 लाख लोगों को ग्रसित करते हैं तथा तीन से साढ़े छह लाख लोग अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं. अन्य जगहों की तरह हमारे यहां भी एक मुश्किल है कि रोगाणुओं का कहर साल के अलग-अलग महीनों में अलग-अलग जगहों पर बरपा होता है. इस हिसाब से ही टीकाकरण और उपचार के इंतजाम होने चाहिए. रोगाणुओं के सक्रिय होने में मौसम और लोगों की स्वास्थ्य की दशा की अहम भूमिका होती है, तो इन बीमारियों का सामना करने की चुनौती को अलग से न देखकर स्वास्थ्य सेवा की व्यापक तैयारी के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए. देश के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी इलाकों में स्वाइन फ्लू और अन्य रोगाणुजन्य बुखारों से ज्यादा लोग बीमार होते हैं. इन राज्यों में उपचार की पुख्ता व्यवस्था करने के साथ आम लोगों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों को जागरूक बनाने की कोशिशें भी लगातार होनी चाहिए, क्योंकि एक तरह के बुखार के बाद दूसरे तरह की बीमारी आन खड़ी होती है.

देश के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी इलाकों में स्वाइन फ्लू और अन्य रोगाणुजन्य बुखारों से ज्यादा लोग बीमार होते हैं. इन राज्यों में उपचार की पुख्ता व्यवस्था हो, क्योंकि बुखार के बाद दूसरी बीमारी आन खड़ी होती है.

दो महाशक्तियों की नूराकुश्ती

पुष्पेश पंत
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार
pushpeshpant@gma.l.com

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा आईएनएफ (इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज) संधि को तोड़ने की घोषणा ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक अप्रत्याशित संकट पैदा कर दिया है. रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह ऐलान करते देर नहीं लगायी कि बदले हालात में रूस के लिए इस ऐतिहासिक समझौते का पालन करना असंभव है, और वह भी अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए इस तरह के परमाण्विक हथियारों के शोध, परीक्षण और उनकी तैनाती के लिए स्वतंत्र है. पुतिन के अनुसार, अनुबंध रूस ने नहीं तोड़ा. अमेरिका के इकतरफा निर्णय के बाद उसके लिए कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं रह गया है. क्या इसे एक नये शीतयुद्ध की शुरुआत समझा जाये, जिसमें परमाण्विक हथियारों की आत्मघाती अंधी दौड़ कभी भी विश्व को सर्वनाश की कगार तक पहुंचा सकती है?

साल 1988 में रोनाल्ड रीगन एवं मिखाइल गोर्बाचेव के बीच आईएनएफ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें दोनों पक्षों ने यह सहमति बनायी थी कि मध्यम दूरी (500 से 5,500 किमी) तक मारक क्षमता वाले प्रक्षेपास्त्रों की संख्या तत्काल घटायी जायेगी. दोनों महाशक्तियां इन हथियारों के जखीरे को संतुलित रखेंगी और तय से अधिक हथियारों को नष्ट कर देंगी. परस्पर भरोसा बढ़ाने की दिशा में यह अभूतपूर्व ऐतिहासिक कदम था. ये प्रक्षेपास्त्र यूरोप में तनाव के कारण थे, इसलिए इनका निरोध-नियंत्रण तनाव शैथिल्य के लिए निर्णायक समझा जाता रहा है. विश्वव्यापी परमाण्विक अप्रसार अभियान को गतिशील बनाने के लिए यह उदाहरण उपयोगी साबित हुआ. यह भी ज्यादा उल्लेखनीय है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया की इन दो महाशक्तियों के बीच यही एक सामरिक संधि अब तक अक्षत थी.

यहां यह जोड़ना भी जरूरी है कि पिछले चार-पांच वर्षों से यह आशंका मुखर की जाती रही थी कि इस संधि का भविष्य अनिश्चित है. अमेरिकी प्रशासन यह आरोप लगाता रहा है कि रूस अपने देश के वचन का पालन नहीं कर रहा है. वह इस श्रेणी के प्रक्षेपास्त्रों के परीक्षण का काम गुप्त रूप से कर रहा है, उपग्रहों तथा निष्पक्ष पर्यवेक्षकों के माध्यम से निरीक्षण की जो पद्धति तय की गयी थी, उसमें रूस सहयोग नहीं कर रहा है आदि. दूसरी तरफ रूस ऐसे ही अभियोग अमेरिका पर लगाता रहा है. साल 2014 से 2018 तक यही रस्साकशी चलती रही है.

रूस का कहना है कि चीन के पास ऐसे-ऐसे प्रक्षेपास्त्र हैं और इनके खतरे को देखते हुए सिर्फ रूस को ही एकतरफा निशस्त्रीकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. यूक्रेन संकट के विकराल रूप धारण करने तथा इस मोर्चे पर रूसी सैनिक हस्तक्षेप ने भी अमेरिका को बौखला दिया है. सीरिया के गृहयुद्ध में असद के समर्थन के कारण भी अमेरिका की चिंताएं बढ़ी हैं. समस्या की जटिलता के अन्य कारण भी हैं.

रूस का मानना है कि परमाण्विक अप्रसार के बारे में अमेरिका दोहरे मानदंड अपनाता है. पाकिस्तान हो या उत्तरी कोरिया, वह इन देशों की परमाण्विक तस्करी की तरफ आंखें मूंदे रहा है. यह जगजाहिर होने पर भी कि किम जोंग-उन अमेरिका को दिये आश्वासनों को नकार आज भी परमाण्विक अस्त्रों से सज्जित मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, ट्रंप उस उद्दंड निरंकुश देश के साथ राजनयिक संवाद जारी रखने को उत्सुक हैं. रूस का आरोप यह भी है कि आईएनएफ संधि का उल्लंघन पहले अमेरिका ने ही किया, जब उसने मोटर वाहनों पर छोटे-छोटे प्रक्षेपास्त्र रख आईएनएफ को झुठलाने की रणनीति अपनायी.

> आईएनएफ पिछले दशक से ही मृतप्राय रही है, इस घड़ी ट्रंप और पुतिन की नूराकुश्ती उसके देहांत की औपचारिक घोषणा भर है, जिससे संसार सर्वनाश की कगार तक अचानक नहीं पहुंच गया है.

मौजूदा संकट को अच्छी तरह समझने के लिए इस बात को रेखांकित करना जरूरी है कि ट्रंप एकाधिक बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि अटलांटिक बिरादरों को अपनी सुरक्षा के खर्च में हाथ बंटाना होगा. भविष्य में ये यूरोपीय देश निःशुल्क अमेरिकी परमाण्विक छत्रछाया का सुख नहीं भोग सकते. दूसरे शब्दों में, अगर शस्त्रों की नयी दौड़ शुरू होती भी है, तो उसका कमरतोड़ बोझ अमेरिका की तुलना में रूस पर कहीं अधिक पड़ेगा! विद्वानों का मानना है कि 1980 वाले दशक में सोवियत संघ को खस्ताहाल बना दिवालियेपन की कगार तक पहुंचाने के लिए रोनाल्ड रीगन ने 'स्टार वार्स' का मायाजाल रचा था, पुतिन को कमजोर करने के लिए ट्रंप यही रणनीति अपना रहे हैं. आज का अमेरिका खुद मंदी की चपेट में है और पुतिन-राज वाला रूस अराजकता और टूट से आतंकित हताश राज्य नहीं है. पुतिन के तेवर आक्रामक और जुझारू हैं तथा वह पहले पलक झपकानेवाले नहीं. इससे कुछ विश्लेषक यह नतीजा निकालने की उतावली कर रहे हैं कि परमाण्विक हथियारों की खतरनाक दौड़ दोबारा शुरू हो चुकी है.

दोनों महाशक्तियां यह जानती हैं कि परमाण्विक हथियारों के प्रयोग की परिणति उभयपक्षीय परमाण्विक सर्वनाश में ही हो सकती है. इसे अंग्रेजी में 'मैड' (म्युचुअली अस्योर्ड डिस्ट्रक्शन) का नाम दिया गया है. आतंक का संतुलन ही हिरोशिमा-नागासाकी से आज तक संसार को परमाण्विक विस्फोट से निरापद रखने में कामयाब रहा है. यह उपलब्धि किसी संधि की नहीं. असल में 'स्टार्ट' या 'सौल्ट' नामक संधियां या वैश्विक स्तर पर परमाण्विक अप्रसार को लागू करवानेवाली 'पार्शियल' या 'कंप्रिहेंशियल टेस्ट बैन ट्रिटी' आदि संधियों का शिकंजा भारत जैसे उदीयमान परमाण्विक देशों को पंगु बनाने के लिए कसा जाता रहा है.

आतंक के संतुलन के कारण अमेरिका तथा रूस का शक्ति-संघर्ष परोक्ष रूप से किसी निर्णायक महासंग्राम में नहीं, क्षेत्रीय मोर्चों में जारी रहा है. एक-दूसरे के मर्मस्थल पर संहारक वार करने की क्षमता वाले प्रक्षेपास्त्र मध्यम दूरी वाले ये हथियार नहीं, वरन अंतरमहाद्वीपीय (इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल) हैं, जिन्हें लड़ाकू बमबार विमानों तथा समुद्र के गर्भ में अदृश्य और सदैव चलायमान पनडुब्बियों में तैनात किया गया है. पहला वार करने का दुस्साहसी यह जानता है कि इसे झेलने के बाद भी सर्वनाशी जवाबी हमला करने की क्षमता घायल शत्रु की बची रहेगी. अगर शांति बरकरार रही है, तो परमाणु हथियारों से संपन्न महाशक्तियों के जिम्मेदार आचरण के कारण नहीं, बल्कि इसी डर से.

दरअसल, आईएनएफ पिछले दशक से ही मृतप्राय रही है, इस घड़ी ट्रंप और पुतिन की नूराकुश्ती उसके देहांत की औपचारिक घोषणा भर है, जिससे संसार सर्वनाश की कगार तक अचानक नहीं पहुंच गया है.

सांप्रदायिक चश्मे से न देखें संस्कृत को

आरके सिन्हा
सदस्य, राज्यसभा
rk.shore.s.nha@sansad.n.c..n

> संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की अतिप्राचीन, समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा है. आधुनिक भारतीय भाषाएं संस्कृत से ही उत्पन्न हुई हैं. इतनी समृद्ध भाषा को कोई व्यक्ति सांप्रदायिक कैसे कह सकता है?

देश का वातावरण इस हद तक विषाक्त हो चुका है कि अब संस्कृत भाषा को भी सांप्रदायिकता के चश्मे से देखा जा रहा है. अब केंद्रीय विद्यालयों में प्रतिदिन सुबह होनेवाली प्रार्थना पर भी निशाना साधा जा रहा है. कहा जा रहा है कि यह संस्कृत प्रार्थना धर्मनिरपेक्ष भारत में नहीं होनी चाहिए. वह दिन दूर नहीं है, जब केंद्रीय विद्यालय के ध्येय वाक्य पर भी सवाल खड़े किये जायेंगे.

केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना तब हुई, जब मोहम्मद करीम छागला देश के शिक्षा मंत्री थे. उन्होंने ईशावास्योपनिषद् के श्लोक 'हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्, तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये' से ही केंद्रीय विद्यालयों का ध्येयवाक्य 'तत्वंपूषण अपावर्णु' को चुना, जिसका अर्थ है- सत्य जो अज्ञान के पर्दे से ढंका है, उस पर से पर्दा उठा दो.

इस प्रार्थना के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल हुई है. इंडोनेशिया की जलसेना का ध्येय वाक्य 'जलेष्वेव जयामहे' यानी 'जल में ही जीतना चाहिए' है. जब इस्लामिक देश को संस्कृत से परहेज नहीं है, तब भारत में संस्कृत की प्रार्थना पर ऐतराज क्यों? भारतीय सेना के तीनों अंगों के ध्येय वाक्य भी संस्कृत में हैं. तो क्या ये सब सांप्रदायिक हैं? दरअसल, देश में जनता का सेकुलरिज्म की ओवरडोज पिलायी जा रही है. देशभर में 1,128 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें एक जैसी यूनिफॉर्म और एक जैसा ही पाठ्यक्रम है. यह दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल चेन है. रोज लगभग 12 लाख बच्चे यही प्रार्थना करते हैं. पिछले साढ़े पांच दशकों में करोड़ों छात्र केंद्रीय विद्यालय से यही प्रार्थना से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं. क्या याचिकाकर्ता ने भारत के करोड़ों नागरिकों की भावना पर ठेस नहीं पहुंचायी है? क्या इसके लिए आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए? इन स्कूलों ने देश को एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं दी हैं. इसे शुरू करने के मूल में विचार भी यही था, ताकि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को कर्मियों के ट्रांसफर की स्थिति में नये शहर में जाने पर केंद्रीय विद्यालय में दाखिला आसानी से मिल जाये.

केंद्रीय विद्यालयों में प्रार्थनाएं वेदों और उपनिषदों से हैं. इसे पूरे विश्व में सभी ने स्वीकार किया है. हमारे मूल संविधान में भी रामायण, महाभारत और उपनिषदों के श्लोकों और चित्रों को ही समाहित किया गया है. इसको दोनों सदनों की लाइब्रेरी और दिल्ली के तीन मूर्ति लाइब्रेरी में भी देखा जा सकता है. मूल प्रति का कवर कमल के पुष्पों के कोलाज से बना है. प्रथम पृष्ठ पर मोहन-जोदड़ो का रेखाचित्र है. प्रत्येक पृष्ठ को प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बसु ने रामायण और महाभारत के प्रसंगों की चित्रकारी से पृष्ठ के दोनों ओर के सुंदर बॉर्डर तैयार किये हैं.

अच्छी बात है कि बीजद के सांसद बी मेहताब ने पिछले सप्ताह लोकसभा में पूछा कि क्या संस्कृत में कुछ बोलना सेकुलर नहीं है? उन्होंने केंद्रीय विद्यालयों में संस्कृत की प्रार्थना को अनिवार्य करने पर निचले सदन में कुछ लोगों के विरोध करने के बाद यह मुद्दा उठाया.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय विद्यालयों में होनेवाली प्रार्थना हिंदुत्व को बढ़ावा देती है. देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के काल में 15 दिसंबर, 1963 को केंद्रीय विद्यालय संगठन स्थापित हुआ था. उस वक्त महान शिक्षाविद् मोहम्मद करीम छागला देश के शिक्षा मंत्री थे. जिस प्रार्थना को सांप्रदायिक माना जा रहा है, उसे सन् 1963 से ही सभी केंद्रीय विद्यालयों में गाया जा रहा है. इससे शिक्षकों या विद्यार्थियों को तो कोई आपत्ति नहीं हुई. केंद्रीय विद्यालयों में की जानेवाली प्रार्थना है- 'असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतमगमय' अर्थात् '(हमें) असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो.' इस प्रार्थना में हिंदू या हिंदुत्व कहां से आ गया है?

केंद्रीय विद्यालय के प्रतीक चिह्न पर एक ध्येयवाक्य है, 'तत्त्वं पूषन्नपावृणु.' यह ध्येय वाक्य यजुर्वेद के ईशावास्योपनिषद् के 15वें श्लोक से लिया गया है. जो ध्येयवाक्य सत्यदर्शन पर आधारित हो, उसे हिंदुत्ववादी कहने का अर्थ है कि बाकी सभी असत्यवादी हैं.

राष्ट्रगान में संशोधन की मांग भी उठती रही है. तो क्या राष्ट्रगान में अधिनायक की जगह मंगल शब्द होना चाहिए? क्या राष्ट्रगान से सिंध शब्द के स्थान पर कोई और शब्द जोड़ा जाये? ऐसी बेकार बातें क्यों की जाती हैं. साल 2005 में संजीव भटनागर ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें सिंध भारतीय प्रदेश न होने के आधार पर जन-गण-मन से निकालने की मांग की थी. इस याचिका को 13 मई, 2005 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरसी लाखोटी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सिर्फ खारिज ही नहीं किया, बल्कि संजीव भटनागर की याचिका को 'छिछली और बचकानी मुकदमेबाजी' मानते हुए उन पर दस हजार रुपये का दंड भी लगाया था.

केंद्रीय विद्यालयों की प्रार्थना पर आपत्ति से साफ है कि देश में कुछ शक्तियां देश को खोखला करने की दिशा में संलग्न हैं. संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की अतिप्राचीन, समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा है. आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे, हिंदी, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि संस्कृत से ही उत्पन्न हुई हैं. इन सभी भाषाओं में यूरोपीय बंजारों की रोमानी भाषा भी शामिल है. बौद्ध धर्म (विशेषकर महायान) तथा जैन मत के भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखे गये हैं. इतनी समृद्ध भाषा को सांप्रदायिक कहनेवाला इंसान सामान्य तो नहीं ही होगा!

बोधि वृक्ष

प्रेम शब्द

प्रेम के बिना आप कुछ भी करें, आप कर्म की संपूर्णता को नहीं जान सकते. अकेला प्रेम ही आदमी को बचा सकता है. लेकिन हम लोग प्रेम में नहीं हैं, हम वास्तव में उतने सहज-सरल नहीं रह गये हैं, जितना हमें होना चाहिए. दूसरों के नाम पर आप अपने स्वार्थों के गर्त में डूबे हुए हैं, आप अपने ही घोंघेनुमा कवच में समाये हैं. आप समझते हैं कि आप ही इस सुंदर संसार का केंद्र हैं. किसी वृक्ष, किसी फूल या बहती हुई नदी को देखने के लिए आप कभी भी नहीं ठहरते और अगर कभी ठहर भी जाते हैं, तो आपके मन में कई विचार, स्मृतियां और जाने क्या-क्या उतर आता है, लेकिन आपकी आंखों में सौंदर्य और प्रेम ही नहीं उमड़ता. प्रेम क्या है? हम यह चर्चा नहीं कर रहे कि प्रेम को क्या होना चाहिए? हम यह देख रहे हैं कि वह क्या है, जिसे हम प्रेम कहते हैं. आप कहते हैं- 'मैं फलां से प्यार करता हूं.' मैं नहीं जानता कि आपका प्रेम क्या है. मुझे संदेह है कि आप किसी भी चीज से प्रेम करते हों. क्या आप प्रेम शब्द का अर्थ भी जानते हैं? क्या प्रेम आमोद-प्रमोद या मजा है? क्या प्रेम ईर्ष्या है? क्या वह व्यक्ति प्रेम कर सकता है, जो महत्वाकांक्षी हो? क्या एक व्यक्ति जो कि प्रतियोगिता में शामिल हो, वह प्रेम में हो सकता है? और आप सब प्रतियोगिता में हैं. सोचिये कि क्या आप नहीं हैं? अच्छे जॉब, बेहतर पद, प्रतिष्ठा, अच्छा घर, अधिक महान विचार, अपनी अधिक सुस्पष्ट छवि बनाने में आप लगे हैं. क्या यह सब प्रेम है? क्या आप तब प्रेम कर सकते हैं, जब आप अपनी ही पत्नी या पति या बच्चों पर प्रभुत्व जमा रहे हों? जब आप ताकत या शक्ति की खोज में लगे हों? तब क्या प्रेम की कोई संभावना बचती है? इन सबको नकारते, अस्वीकार करते हुए हम जहां पहुंचते हैं, वही प्रेम होता है. इसलिए आपको उस सबको नकारना होगा, जो प्रेम नहीं है. जो कि महत्वाकांक्षा ना हो, प्रतियोगिता ना हो, क्रोध या आक्रामकता ना हो, हिंसा ना हो. भले ही यह सब बोलचाल में हो या आपके कृत्यों में या विचारों में, पर न हो.

जे कृष्णमूर्ति

आपके पत्र

प बंगाल में सियासी ड्रामा ओवर

सारधा चिटफंड केस में सीबीआइ जांच पर मचा बवाल सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से थमने की उम्मीद जगी है. कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआइ के सामने पेश होने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के मद्देनजर जांच के विरोध में धरने पर जमे राजीव और नेताओं को यह समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र में व्यवस्थागत प्रक्रियाओं के अतिक्रमण की इजाजत नहीं है. राजीव कुमार पर अदालत की अवमानना की तलवार भी लटक गयी है. सीबीआइ की इस कार्यवाही को केंद्र के निर्देश पर उठाया गया कदम बताया जा रहा है. राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लग गयी. उनसे केवल पूछताछ होगी. बहरहाल केंद्र और राज्य दोनों को अपने हित के लिए ऐसे विवाद को न्योता नहीं देना चाहिए जिससे जांच एजेंसियों की साख और गंभीरता पर सवाल खड़े हो. जांच प्रक्रिया में दखलअंदाजी किसी भी सूरत में उचित नहीं हो सकती है.

अमन सिंह, बरेली, उत्तर प्रदेश

रोजगार में स्थानीय को प्राथमिकता

मध्यप्रदेश के कमलनाथ सरकार का यह फरमान कि राज्य में उद्योग लगाने वालों को 70 फीसदी रोजगार स्थानीय लोगों को देना होगा, एक स्वभाविक घोषणा है. आजादी के बाद से ही कई राज्य ऐसी घोषणा करते रहे हैं. ओडिशा, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल एवं हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य स्थानीय आबादी को 70 से लेकर 90 फीसदी तक रोजगार देने का फैसला ले चुके हैं. इस नीति से किसी को कोई दुख होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिन उद्योग घरानों ने सरकार से सब्सिडी, कर छूट तथा सस्ती जमीन ली है, उन्हें इस नीति का सहयोगी बनना भी चाहिए. उन बीमारू प्रदेशों के लिए यह अभिशाप हो सकता है जिनकी अधिकांश आबादी को बाहर जाकर काम-धंधा खोजना पड़ता है. अगर शत प्रतिशत राज्य, इस नीति को लागू कर दें और इसका दायरा बढ़ा कर थोक एवं खुदरा व्यापार तक कर देंगे, तब बीमारू प्रदेशों के लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा.

जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

राजनीतिक हिंसा बनायेगी नकारात्मक छवि

भारतीय राजनीति में हिंसक घटनाओं को किसी भी तरीके जायज नहीं ठहराया जाना चाहिए. पिछले दिनों बंगाल में बीजेपी की चुनावी रैली के दौरान हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिली. त्रिपुरा में सत्ता परिवर्तन के बाद ऐसा मंजर देखने को मिला. केरल और देश के अन्य भागों में भी राजनैतिक हिंसा की खबरें देखने को मिलती है. आज हम विश्व के बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहे है. विज्ञान में भी अपने झंडे गाड़े हैं. भारत में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते बहुत से देशों के लिए एक आदर्श है. ऐसे में अगर देश के घरेलू राजनीति हिंसात्मक होगी, तो विश्व में हमारी नकारात्मक छवि बनेगी. देश के प्रबुद्धजनों एवं जिम्मेदार नागरिकों, नेताओं को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए.

सुमन कुमार सिंह, रांची

कुछ अलग

'कहां तुम चले गये!'

शफक महजबीन
टिप्पणीकार
mahjabeenshafaq@gma.l.com

एक से बढ़कर एक गजलों और गीतों को नर्म लहजे वाले अंदाज में अपने होठों से छूकर अमर कर देनेवाले और अपनी शहद जैसी आवाज से जग को जीत लेनेवाले गायक जगजीत सिंह जी अगर इस दुनिया में होते, तो आज वे अपना 78वां जन्मदिन मना रहे होते. आज भी उनकी मखमली आवाज का जादू लाखों दिलों को बहुत सुकून देता है.

जगजीत सिंह का जन्म आठ फरवरी, 1941 को श्रीगंगानगर, राजस्थान (तब बीकानेर स्टेट) में हुआ था. हालांकि, मूलतः उनका परिवार पंजाब के रूपनगर जिले (पुराना नाम रोपड़) का रहनेवाला था. उनके बचपन का नाम जगमोहन सिंह था, जिसे बाद में उन्होंने जगजीत सिंह कर लिया. उन्होंने जिंदगी में बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखे.

जगजीत सिंह के पिता इन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन इनकी रुचि संगीत में थी. साल 1965 में जब वे संगीत को अपना करियर बनाने के लिए मुंबई गये, तब वहां उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा और होटलों तक में गाना पड़ा. गजल गायक के रूप में स्थापित होने के बाद उन्हें सबसे बड़ा सदमा तब लगा, जब इनका अठारह साल का बेटा एक हादसे में चल बसा. एक कार्यक्रम में जब वे गजल- 'दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह' गा रहे थे, तो गाते-गाते रोये जा रहे थे. कहते हैं कि दिल से जुड़े अपनों के साथ कुछ बुरा होने की आहट हमें महसूस हो ही जाती है. जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, उनके बेटे की मौत की खबर मिली. फिर तो वे पूरी तरह टूट गये.

जगजीत सिंह की गायकी का अंदाज बिल्कुल अलग था- नर्म, मुलायम, शहद जैसा मीठा, इसलिए लोगों के दिलों में उतरने में इन्हें कोई ज्यादा वक्त नहीं लगा. गजल पेश करने के इनके अंदाज ने गजल को उन आम लोगों तक पहुंचाया, जिन्हें गजलों की समझ कम थी. उन्होंने आसान लफ्जों वाली गजलों को सादगी भरी और सीधा दिल में उतर जानेवाली आवाज देकर अमर कर दिया. एक बार उन्होंने कहा भी था कि 'कलाम सिंपल होना चाहिए, जिससे सुननेवाला आसानी से समझ सके और सुनकर उसे आराम मिले.'

जगजीत सिंह ने गीतकार और शायर निदा फाजली की ज्यादातर गजलें गायी हैं. फिल्म 'सरफरोश' की गजल 'होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है' से लेकर फिल्म 'तुम बिन' की गजल 'कोई फरियाद तेरे दिल में छुपी हो जैसे' तक एक लंबा सिलसिला है. निदा के लफ्ज और जगजीत की आवाज, इस संगीतमय जोड़ी की पूरी दुनिया कायल है. निदा फाजली कहते थे, 'जगजीत की आवाज से मेरी गजलों का रिश्ता तब से है, जब मिर्जा गालिब जवान हुआ करते थे.'

पद्मभूषण जगजीत सिंह की मखमली आवाज वाद्यों की स्वरलहरियों के साथ घुलकर श्रोताओं के कानों में मिसरी घोल देती है. ब्रेम हेमरेज के चलते अस्पताल में इन्होंने अपनी आखिरी सांस 10 अक्तूबर, 2011 को ली. गजल प्रेमियों के दिलों में इन्हें लेकर यह सवाल हमेशा रहेगा- 'चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गये!'

देश दुनिया से

फ्रांस-जर्मनी के बीच ऐतिहासिक संधि

पिछली शताब्दी में, फ्रांस और जर्मनी के संबंधों में नाटकीय उतार-चढ़ाव आते रहे हैं, जिसमें शत्रुता से लेकर सुलह और सहयोग शामिल है. बीते 22 जनवरी को फ्रांस और जर्मनी ने आचेन में एक नयी मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किया. प्राचीन शहर आचेन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दोनों देशों द्वारा साझा की जाती है. संधि पर हस्ताक्षर के ऐतिहासिक मौके पर दोनों देशों ने एकीकरण के मार्ग पर आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प लिया. 'अमेरिकन फर्स्ट' अभियान की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के बढ़ते चलन का मुकाबला, अंतरराष्ट्रीय संघ का निर्माण करने और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना, इस संधि का उद्देश्य है. फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को उम्मीद है कि यह संधि यूरोपीय संघ के सामंजस्य को बढ़ायेगी और राष्ट्रवाद व लोकलुभावनवाद के कारण बढ़ती आक्रामकता का विरोध करेगी, साथ ही यह बाहरी खतरों से यूरोपीय संघ की जनता की रक्षा भी करेगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यूरोपीय संघ अमेरिका द्वारा परित्यक्त महसूस करता है. इसके अलावा, यूरोपीय संघ का मानना है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा बाहरी दबाव है. यह स्थिति यूरोपीय देशों को एकजुट होने का आह्वान करती है.

जियांग फेंग

कार्टून कोना

साभार : डान, पाकिस्तान

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar..n पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है